

STL GLOBAL LIMITED

Date: 15th February, 2022

From: STL Global Limited

Scrip Code: 532730

To

The Listing Compliance Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai 400 001, MH

Sub: Intimation of Newspaper Publication of Un-Audited Financial Results for the quarter & nine months ended 31st December, 2021

Dear Sir/Madam.

Pursuant to Regulation 47 and other applicable Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, please find enclosed herewith copies of newspaper clippings of the advertisement published on the above-mentioned subject matter, in the following newspaper:

- Mint English in all Edition on 14th February, 2022
- 2. Veer Arjun Hindi in Delhi Edition on 13th February, 2022

Kindly take the above information on your record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours truly,

For STL GLOBAL LIMITED

Manil Kr. Nagar

Company Secretary

Encl: As above

देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं :भूपेन्द्र यादव

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने त्रैमासिक रोजगार सर्वे (क्युईएस) तथा ईपीएफओ पेरॉल डाटा की हाल की सर्वे रिपोर्टों को उल्लेखित करते हए कहा कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कामगारों एवं श्रमिकों के कल्याण के लिए

आज दोपहर गुरुग्राम में ईएसआईसी की 187वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईएसआईसी अस्पतालों द्वारा श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी तथा फैक्ट्रियों/एमएसएमई कलस्टरों को एक यूनिट समझा जाएगा तथा ईएसआईसी श्रमिकों की बचाव संबंधी स्वास्थ्य जांच के लिए उनके साथ समन्वय करेगा। वर्तमान में जारी प्रायोगिक परियोजना के हिस्से के रूप में कुल 15 शहरों में स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया जाएगा।भूपेन्द्र यादव ने यह भी बताया कि ईएसआईसी की लंबित परियोजनाओं तथा ईएसआईसी के अस्पतालों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी तथा चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपलब्धता का



गुरुग्राम में ईएसआईसी की 187वीं बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव।

ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने चिकित्सकों से निर्धनों की सेवा करने वाले ईएसआईसी अस्पतालों में नियुक्त होने की अपील की तथा आश्वासन दिया कि चिकित्सकों तथा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में ईएसआईसी कॉरपोरेशन द्वारा संशोधन किया जाएगा। ईएसआईसी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि शीघ्र ही एक

खुली, डिजिटल तथा पारदर्शी स्थानांतरण नीति लाग् की बीते एक दिन में कोविड-19 के जाएगी। श्री यादव ने दो ईएसआईसी प्रबंधन डैशबोर्डों अर्थात् निर्माण परियोजना डैशबोर्ड तथा अस्पताल डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य डैशबोर्ड ईएसआई अस्पताल के निष्पादन से संबंधित प्रमुख सूचना की झलक प्रदर्शित करेगा। यह दर्शकों को अस्पताल डैशबोर्ड पर वर्तमान ऑक्यूपेंसी तथा ओपीडी में रोगियों की संख्या की सूचना भी उपलब्ध कराएगा। निर्माण डैशबोर्ड ईएसआईसी की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के बारे में मुख्य सुचना उपलब्ध कराएगा। श्री यादव ने जोर देकर कहा कि दोनो डैशबोर्ड न में कोविड-19 से 804 और लोगों केवल बेहतर निगरानी में सहायता करेंगे बल्कि इनका परिणाम दक्ष एवं प्रभावी कार्यान्वयन के रूप में भी सामने आएगा। इस अवसर पर श्री यादव ने 2021 के पैरालिम्पिक्स स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत तथा रजत पदक विजेता सुश्री भविना पटेल को बधाई दी एवं उन्हें सम्मानित किया। उन्हें क्रमशः एक करोड़ रुपए तथा 50 लाख रुपए के चेक तथा प्रशस्ति पत्र दिए गए। दोनों खिलाडियों ने मंत्री तथा ईएसआईसी को सतत समर्थन के

वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 6,10,443 रह गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश की मौत के बाद, संक्रमण से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,07,981 हो गई। देश में पिछले छह दिन से कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की संख्या एक लाख से कम बनी हुई है।

नई दिल्ली, (भाषा)। भारत में

50,407 नए मामले सामने आने के

बाद देश में संक्रमितों की संख्या

बढ़कर 4,25,86,544 हो गई।

देश में अभी 6,10,443 कोरोना वायरस संक्रमितों का

नई दिल्ली। कर्नाटक में जारी

हिजाब विवाद के बीच उच्चतम

न्यायालय में शनिवार को एक

जनहित याचिका दायर की गयी

जिसमें समानता और भाईचारे को

बढावा देने तथा राष्ट्रीय अखंडता के

वास्ते पंजीकृत शिक्षण संस्थानों में

कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के लिए

समान पोशाक संहिता लाग करने

का केंद्र सरकार, राज्यों और

वर्गीकृत विज्ञापन

Change of Name

I, hitherto known as Shweta

कुल मामलों का 1.43 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 87,359 की कमी दर्ज की गयी। देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.37 प्रतिशत है।

भारत में कोरोना के 50,407 नए मामले आए सामने

अद्यतन आंकडों के अनुसार, संक्रमण की दैनिक दर 3.48 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 5.07 प्रतिशत दर्ज की गई। देश में अभी तक कुल 4,14,68,120 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है। वहीं, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 172.29 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि देश में सात अगस्त 2020 को इलाज चल रहा है, जो संक्रमण के संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 के 804 मामले सामने आए।

अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड के पार और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले चार करोड़ के पार पहुंच गए। मंत्रालय के आंकडों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से मौत

मामले का संज्ञान लिया था और

कहा था कि यह प्रत्येक नागरिक के

संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित

मामले की सुनवाई करेगी। इस

करेगी और उचित समय

देश में निजी क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता : वित्त राज्य मंत्री

डॉ. भागवत कराड ने शनिवार को कहा कि देश में चल रही निजी क्रिप्टोकरेंसी वैध नहीं है और भविष्य में इसकी वैधानिक स्थिति के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं

संवाददाताओं से कहा, भारत में (निजी) क्रिप्टोकरेंसी को रिजर्व बैंक या सरकार की ओर से कोई मान्यता नहीं दी गई क्रिप्टोकरेंसी देश में फिलहाल वैध नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वह अभी नहीं बता सकते कि भविष्य में निजी क्रिप्टोकरेंसी को वैध किया जाएगा या नहीं? उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सरकार प्रति लीटर की कटौती की थी। तब के शीर्ष स्तर पर चर्चा होने के बाद प्रधानमंत्री ने देश के तमाम

ही कुछ कहा जा सकेगा। कराड ने कहा, ऐसी खबरें हैं कि कछ लोगों ने (निजी) क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है। लिहाजा क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन से अर्जित लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव हाल ही में पेश आम बजट में किया गया है। वित्त राज्य मंत्री ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या वह जनता को आश्वस्त कर सकते हैं कि पांच राज्यों के विधानसभा चनावों के बाद पेटोल-डीजल के दामों में इजाफा नहीं होगा? उन्होंने

कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले

साल दीपावली पर पेटोल और

डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की

दरों में क्रमश: पांच और 10 रुपये

मुख्यमंत्रियों से आह्वान किया था कि वे भी पेट्रोलियम पदार्थों पर राज्यों के कर घटाएं।

कराड ने भाजपा के विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां तो (प्रधानमंत्री के आह्वान पर) पेट्रोल-डीजल पर कर घटा दिए गए। लेकिन गैर भाजपा शासित सुबों में पेट्रोलियम पदार्थों पर करों में कटौती नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा महाराष्ट में पेटोल-डीजल के दाम बहुत ज्यादौ हैं। गौरतलब है कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

त्रिपुरा में एनएलएफटी के सात उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण

अगरतला, (वार्ता)। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) के कुल सात उग्रवादियों ने विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि एनएलएफटी के कम से कम पांच उग्रवादियों ने उत्तरी त्रिपुरा के आनंदबाजार शिविर में असम राइफल्स के सामने आत्मसमर्पण किया, जबकि उसी गुट के दो अन्य शासित मध्यप्रदेश की तलना में लोगों ने उत्तरी त्रिपरा में त्रिपरा पुलिस की विशेष शाखा के सामने हथियार डाल दिए। पुलिस ने कहा मध्यप्रदेश के पड़ोसी महाराष्ट्र में कि आत्मसमर्पण करने वाले पांच उग्रवादियों की पहचान रामबादल (एनसीपी) और कांग्रेस की त्रिपुरा (40), जलाक्सा त्रिपुरा (38), जबा रंजन त्रिपुरा (38) और

'कम्युनल टिफिन' में 'सेक्युलर टमाटर' का 'सियासी टशन' टांय-टांय फिस्स हो चुका : नकवी

रामपुर, (वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 'कम्युनल गीत' पर 'सेक्युलर संगीत का ट्रेलर', 'चुनावी बूथ' पर पिट चुका है। श्री नकवी ने आज यहाँ के ज्वाला नगर, सिविल लाइन्स एवं अन्य क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों को सम्बोधित संवैधानिक प्रतिबद्धता है। करते हुए कहा कि 'कम्युनल टिफिन' में 'सेक्युलर टमाटर' का 'सियासी टशन' टांय-टांय फिस्स हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक प्रतिबद्धता है जबिक 'छद्म सेक्युलर सियासी सिंडिकेट' के लिए 'सियासी सविधा का साधन' है। भाजपा

अल्पसंख्यकों के शोषण की 75 शतरंजी चालें'' चली हैं। कभी भय की चाल, कभी भ्रम की ढ़ाल, कभी धर्म का जाल तो कभी अफवाहों-आशंकाओं के बवाल से वोटों का अपहरण करते रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास', समावेशी संकल्प और

मोदी-योगी सरकार समाज के सभी वर्गों के 'सम्मान के साथ सशक्तिकरण' के रास्ते पर मजबूती और पूरी ईमानदारी से चल रही है। श्री नकवी ने कहा कि समाज को ऐसे 'सियासी सौदागरों' से होशियार रहना होगा जो 'धर्मनिरपेक्षता का चोला, वोटों के अपहरण के खेला' के 'पेशेवर खिलाडी' हैं। भाजपा के लिए

'सबका साथ, सबका विकास' वोटों की राजनीति नहीं, 'विकास की राष्ट्रनीति' है।

श्री नकवी ने कहा कि 'छद्म धर्मनिरपेक्ष्रता और तृष्टीकरण के राजनैतिक छल' को श्राजपा द्वारा 'समावेशी विकास के बल' से ध्वस्त होने से '3बी ब्रदरहुड' (बलवाई-बाहुबली-बकैर्स) बौखलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रभानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृष्टीकरण, परिवारवाद, धर्म, जाति, क्षेत्रवाद के राजनीतिक स्पीड ब्रेकर को ध्वस्त कर 'समावेशी सशक्तिकरण' का हाईवे तैयार किया है। मोदी-योगी का 'सर्वस्पर्शी विकास' का संकल्प ही समाज के हर तबके की 'आँखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली' की

झूठे दावों में व्यस्त रहने के आदी हो गए हैं योगी : प्रियंका

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्नाव की पीड़ित युवती का शव मिलने की बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य मे महिलाओं पर अत्याचार कर उनकी हत्या कर दी जाती है लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ झुठे दावों में ही व्यस्त रहते हैं। श्रीमती वाड्रा ने शनिवार को यहां एक बयान में कहा, ''उन्नाव में जो घटा वो उत्तरप्रदेश में नया नहीं है। एक दलित लडकी की मां अपनी बेटी का पता लगाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटती रही, अंत में उसको अपनी बेटी का शव मिला। प्रशासन ने उसकी एक नहीं सुनी। भाजपा को इस मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय जवाब देना चाहिए कि प्रशासन क्यों उस मां को जनवरी से दौड़ाता रहा। किसी ने इस बिटिया की मां की गुहार नहीं सुनी।'' उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, ''योगी आदित्यनाथ जी आप अपने भाषणों में कानून व्यवस्था की बात करना छोड़ दीजिए।

अल्पसंख्यक वोटों के 'सियासी सौदागरों' ने बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी के आधार पर दावें से इकार नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

विधि संवाददाता

नेता ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों में

नई दिल्ली। ट्रक चोरी से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्टने कहा है कि बीमा कंपनी को चोरी की जानकारी देने में देरीके आधार पर दावे से इनकार नहीं किया जा सकता. यदि चोरी की घटना की एफआईआर दर्ज करा दी गई है। यह महत्वपूर्ण फैसला एक कंपनी की उस अपील पर आया, जिसकी बीमित ट्रक को चार नवंबर2007 को लूट लिया गया था और पुलिस ने अगले दिन दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन ट्रक बरामद नहीं हो सका था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बीमा दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि ट्रक चोरी की घटना की जानकारी एक दिन बाद दी गई थी। बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के यहां मुकदमा जीत लिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला

एम त्रिवेदी की बेंच ने एनसीडीआरसी के फैसले को निरस्त करते हुए कहा था कि महज बीमा कंपनी को सूचना देने में विलंब करने से दावा खत्म नहीं हो सकता, यदि त्रंत एफआईआर दर्ज करा दी गई हो। बेंच की ओर से जस्टिस त्रिवेदी ने फैसला लिखा। मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए फैसले में कहा गया है कि आईना कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ट्रक चोरी की एफआईआर अगले दिन तत्काल दर्ज कराई गई थी और अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया था एवं आरोप पत्र भी दायर किए गए थे। फैसले में कहा गया है कि बीमा दावा महज मामला दर्ज कराने में देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था और जब एफआईआर त्रंत दर्ज कराई गई तथा कानून ने अपना काम करना शुरू कर दिया तो बीमा कंपनी केवल इस आधार पर दावा खारिज नहीं कर सकती कि चोरी की घटना के बारे में जानकारी देने में देरी हुई थी।

विशेषज्ञों की सिफारिश पर 5-15 आयु वर्ग के टीकाकरण पर फैसला लिया जाएगा : माडविया

गांधीनगर, (भाषा)। केंद्रीय स्वास्थ्य मनसुख मांडविया ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार विशेषज्ञों से सिफारिश मिलने पर जल्द से जल्द पांच से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान

मांडविया ने यहां पत्रकारों से यह बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि पांच से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण पर सरकार का क्या रुख है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के समूह ने अभी तक इस आयु वर्ग के टीकाकरण पर कोई सिफारिश नहीं दी है। केंद्रीय मंत्री एक फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने यहां आए थे। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, कब और किस आयु वर्ग को टीके की खुराक देनी है, इसका फैसला वैज्ञानिकों के समूह की सिफारिश के आधार पर लिया जाता है। हमने एक सप्ताह के भीतर एहतियाती समूह के लिए उसकी सिफारिश को लागू किया था। हम पांच से 15 वर्ष आयु वर्ग के लिए भी उसकी सिफारिश मिलने पर उसे निश्चित रूप से लागू करेंगे। देश में 15-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान पिछले



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया

महीने शुरू हुआ था। मांडविया ने कहा, आज टीकाकरण कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास पर्याप्त टीके हैं, खुराकों की कोई कमी नहीं है। हम वैज्ञानिक समुदाय की सिफारिश को निश्चित रूप से लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को अभी तक ऐसी कोई सिफारिश नहीं मिली है और इस संबंध में फैसला आने वाले दिनों में लिया जाएगा तथा यह कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। मांडविया ने कहा कि पिछले साल जुलाई-अगस्त में सीरो सर्वेक्षण से पता चला कि 67 प्रतिशत बच्चों में भी एंटीबॉडीज बनीं और बच्चों में बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आखिरकार ये जैविक चीजें हैं, इसलिए सिफारिश करने से पहले

वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। पहले हम टीकाकरण के संबंध में सिफारिशों के लिए दुनिया का अनुसरण करते थे। आजे हमारे वैज्ञानिक अपना विश्लेषण करते हैं, उनेका अपना अध्ययन है और इस आधार पर राय बनाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने तीसरी लहर के दौरान महामारी से लड़ने के लिए टीकाकरण का बहुत प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर टीकाकरण से भारत को तीसरी लहर से निपटने में मदद मिली। मांडविया ने कहा कि 15-18 वर्ष आयु वर्ग के 75 फीसदी बच्चों ने कोविड-19 रोधी टीके की ख़ुराक ले ली है और 96 फीसदी वयस्कों को पहली खुराक तथा 77 फीसदी को दोनों ख़ुराक मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अध्ययनों से पता चला है कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण ने ज्यादातर लोगों की मदद की है और इसके परिणामस्वरूप देश संक्रमण के मामलों में कमी लाने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, इन सभी के आधार पर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि भारत कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए बहुत प्रभावी तरीके से टीकाकरण का इस्तेमाल करने में सफल रहा है।

खजेंद्र रियांग (36) के रूप में हुई है, जो आनंदबाजार के सूर्यहमपारा गांव के रूप में की गयी हैं जबकि धलाई जिले के मनु में रमनी कुमार पारा के रहने वाले स्वप्न त्रिपुरा

(16) को एनएलएफटी के स्वयंभू कमांडर परिमल देबबर्मा ने साल 2020 में भर्ती किया था। सूत्रों ने कहा कि दो साल तक समाज से अलग-थलग जंगलों में रहकर संघर्ष भरा जीवन जीते-जीते आखिरकार निराश होकर उन्होंने संगठन छोडने का फैसला किया और तीन दिन पहले बंगलादेश के अपने शिविर से भाग निकले।

Public Notice

W/o Late Raikumar Sabharwal R/o F No. 1/9171, 1st Floor, Gali No. 4, Wes Rohtas Nagar, Shahadara Delhi evered all relation and disowned m nd Bhanvi Sabharwal from my al ovable/immovable properties due t heir misconduct. My client shall no responsible for their acts/deed. . K. Verma, Advocate, Chambe No. 384, Lawyers Chambers, Sake Court, New Delhi.

Particulars

Total Expenses

Total Income from operations (net)

Net Profit /(Loss) for the period

(before Tax, Exceptional Items)

Net Profit /(Loss) for the period

Net Profit /(Loss)for the period after

period (Comprising Profit/(Loss) for

the period (after tax) and Other

Face Value: Rs. 10/- each)

Equity Share Capital

Sheet of previous year

Diluted

Comprehensive Income (after tax)

Reserves (excluding Revaluation

Reserve) as shown in the Balance

Earnings Per Share (for continuing

and going concern assumptions.

Place: Faridabad Date: 12th February, 2022

केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

हिजाब विवाद : सुप्रीम कोर्ट में समान पोशाक

संहिता के लिए जनहित याचिका दायर

शीर्ष अदालत के समक्ष हिजाब विवाद से संबंधित अन्य मामलों का उल्लेख शुक्रवार को त्वरित सुनवाई के लिए किया गया था, जिसने कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन-सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष लंबित PUBLIC NOTICE

SC No.250/21 BHANU YADAV Vs. STATE & ORS.

esent:

Siv Sagar Sharma, Ld. Counsel for the petitioner
ong with petitioner. The petitioner is directed to file
amended memo of parties reflecting that the
spondent no. 1 State (Govt. of NCT of Delhi) shall be spondern no. 1 State (sowt. or NCI of Delini) shall or presented through the concerned SDM, Delhi. Upon ing of PF/RC, issue notice of this petition to the SDM noncemed on filling of PF for filling survivorship rifficate of deceased for NDOH. Let notice be also sued to concerned banks i.e. respondent no. 4 to 8 for ing details of assets of deceased on filling of PF made dent no. 2 and 3 on filing of PF made retu NDOH. Also, issue notice to this petition to the

s shall be returnable on 15.03.2022 (Sheetal Chaudhary Pradhan) ACJ/CCJ/ARC (South-East), Saket, New Delhl/24.12.2021

Sahu @ KM. Ranu D/o Ram Bilas Kumar @ Ram Bilas Sah R/o C-104/C1, Paryavaran Complex, South Delhi-110030 have changed my name and my father's Name and shall hereafter be known as "Shweta Sahu and Father's Name as Ram Bilas

Correspondin

Quarter ender

vear (31.12.2020

2,483.01

122.99

122.99

122.99

2,722.18

0.46

0.46

Nine Month

(31.12.2021)

Unaudite

9,068.42

8,890.7 249.31

249.31

226.81

218.97

2,722.18

0.81

For and on behalf of the Board of Directors of

STL GLOBAL LIMITED

CIN: L51909DL1997PLC088667

Read, Office: Unit No. 111, Block No. 1, First Floor

Tel: 011-26935829, E-mail: investors@stl-global.com, Website: www.stl-global.com

Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER & NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2021

31.12.2021

Unaudited

3,375.23

3,279.41

96.46

96.46

96.46

96.75

0.36

The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the

quarter and nine months ended on December 31, 2021filed with the Stock Exchange

i.e. NSE & BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosur Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time. The full formats of the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31

2021are available on the company's website at www.stl-global.com and on the Stoc Exchanges websites at BSE at www.bseindia.com and at NSE at www.nseindia.com

The Company has analyzed all the relevant parameters associated with the risk due t COVID-19 and is of the opinion that it will not have any material impact on the busines

There were no exceptional and extraordinary items during the quarter and nine month ended 31st December, 2021. For and on behalf of the Board of Directors of

पूर्वोत्तर रेलवे

Kmail: dycmmgkpd@gmail.com bshe:www.ner.indianrailways.gov. निविदा सूचेपा संख्या: 34 दि. 11-02-2022 -प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा आमंत्रण

प मुख्य सामग्री प्रबंधक / डिपो / पूर्वोत्तः रातवे / गोरखपुर कृते भारत के राष्ट्रपति तथ उनकी ओर से ई—प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम र नम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेर् नेविदा आमंत्रित की जाती है। सामग्री का पूर् वेवरण तथा नियम एवं शर्ते वेबसाई www.ner.indianrailways.gov.in www.ner.Indianrailways.gov.in & www.tenders.gov.in पर देखा जा सकता है। क्रम सं.—01, निविदा संख्या एवं खुलने की तिथिः 10206460D खुलने की तिथिः 14-03-2022, मद का संक्षिप्त विवरणः ऐडेस्टल असंबली कार स्लेजिंग बुम बैरिपः इत्यादि ।, मात्राः 2500 Nos., अनेस्ट मनी (रूपया)ः ₹ 68,250/-, क्रम सं.—02, निविदा संख्या एवं खुलने की तिथिः 10225265 खुलने की तिथिः 14-03-2022, मद का संक्षिप्त विवरणः स्पलाई इंस्टालेशन एण्ड कमीशानिंग विवरणः सप्लाई इंस्टालेशन एण्ड कमीशनिः ऑफ प्रेशराइज्ड फलशिंग सिस्टम फार नान—एसी एल.एच.बी. कोच इत्यादि। मात्रा 1480 Set, अर्नेस्ट मनी (रूपया): ₹ 10,39,980/-, क्रम सं.—03, निविदा संख्या एवं खुलने की तेथि: 11225218 खलने की तिथि: 11-03-2022 मद का संक्षिप्त विवरणः सेट ऑफ मेगनेटिव पथ फार् क्यू टी ए–2 रिले इत्यादि। मात्राः 3630 Set, अर्नेस्ट मनी (रूपया)ः ₹1,64,910/-(1) उपरोक्त निविदा आईआरईपीएस रा, उन्तर्या ानाया आञ्चलारहपार्श्त क साइट http://www.ireps.gov.in पर स्थित है जो प्रतिष्ठान इलेक्ट्रानिकली पंजीकृत है वे ई-टेण्डर में सम्मिलित हो सकते हैं। जो प्रतिष्ठान क्लास-3 डिजिटल सर्टिफिकेट हीं प्राप्त किये हैं। अधिकृत एजेन्सी भार सरकार के द्वारा अधिकार पत्र आईर्ट अधिनियम 2000 से अधिकृत है उनसे प्राप्त कर सकते है। मैन्युअल निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। (2) आपूर्तिकर्तागण को यह सूचित किया जाता है कि उप मुख्य सामग्री प्रबन्धंक / डिपो पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपु विज्ञापित निविदाय सभी बुलेटिन निविदाय केवल ईपीएस (ई–प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम) द्वार खोली जा रही है, जो भी प्रतिष्ठान उप मुख्य सामग्री प्रबन्धंक / डिपो पर्वोत्तर रेलवे गेरखपुर की निविदाओं के प्रति इच्छुक हो एव माग लेंना चाहते हो उन्हें आवश्यक डिजिट**्** संग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा भपने प्रतिष्ठान को CRIS/New Delhi जीकृत कराना होगा। इस सम्बन्ध में आवश्य विस्तृत विवरण वेबसाइंट http://www.ireps gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। (3) निविद सूचना के अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रकाशन में मिन्नत र्गने की स्थिति में अंग्रेजी प्रकाशन मान्य होगा (4) एलोकेशन शीर्ष निविदा प्रपत्र, जमानत राणि का 00844517 तथा बयाना धनराणि का 00844506 है। **(5)** उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/डिपो/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा

ोगा। यह Global Tender पर प्रभावी नहीं होगा। / उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/डिप र्जाधि/एस—101 गोरखपुः यात्री स्पूर्वधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो० नं० 09794845955 पर एसएमएस करें। ।।ड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

काशित ई-निविदाओं का टेण्डर कास्ट तथ

एमडी का भगतान आन—लाइन IREPS Porta

ही मान्य होगा जो दिनांक 01-09-2016

या उनके बाद प्रकाशित निविदाओं पर प्रभाव

8cm x 1/8cm मेयर एपरेल लिमिटेड CIN: L18101HR1993PLC032010

STL Global Limite

(DIN: 00227254

Sh. Sanjiv Kumar Aggarwa (Whole Time Director)

पंजीकृत कार्यालयः नं. 3 एवं 4, मुस्तिल नं. 19, किला नं. 5, टाटा कंसल्टेंसी के सामने, एनएच—8, गांव नरसिंहपुर गुरूग्राम—122004 हरियाणा, भारत फोनः 91–9953696916, ई–मेलः info@meyerapparel.com, वेबसाइटः www.meyerapparel.com 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

<u> </u>	Ten to moment of a final famous \$1. If the first		W 144014 11	V II II 41 VI		v. (II or 1	
क्र.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त	समाप्त वर्ष	
सं.		31.12.2021 अलेखापरीक्षित	30.09.2021 अलेखापरीक्षित	31.12.2020 अलेखापरीक्षित	31.12.2021 अलेखापरीक्षित	31.12.2020 अलेखापरीक्षित	30.3.2021
		अलखापरााक्षत	अलखापराक्षित	अलखापरााक्षत	अलखापरााक्षत	अलखापरााक्षत	लेखापरीक्षित
	प्रचालनों से कुल आय	124.85	228.05	163.79	396.44	184.69	349.31
2	अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर, अपवादात्मक और / या	(35.36)	5.21	(18.53)	(50.57)	(163.43)	(144.63)
	अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)						
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक	(35.36)	5.21	(11.92)	(50.57)	(164.31)	(144.63)
1	और / या अतिविशिष्ट मदों के बाद)						
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक	(35.36)	5.21	(11.92)	(50.57)	(164.31)	(144.63)
1	और / या अतिविशिष्ट मदों के बाद)						
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि)	(36.11)	5.05	(3.99)	(51.06)	(162.37)	(153.15)
1	(कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल						
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 3/– प्रत्येक)	2,426.67	2,426.67	2,426.67	2,426.67	2,426.67	2,426.67
7	अन्य इक्विटी						(5,140.10)
8	प्रति शेयर अर्जन (रु. 3 / – प्रत्येक)						
	मूल	(0.04)	0.01	(0.01)	(0.06)	(0.20)	(0.18)
1	तनुकृत	(0.04)	0.01	(0.01)	(0.06)	(0.20)	(0.18)

टिप्पणी: 1. ये परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित उसके संगत नियमों और भारत में सामान्यतया स्वीकार्य अन्य लेखाकरण सिद्धांत अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) के अनुरूप तैयार किये गये हैं। 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए कम्पर्न 5 उपरोक्त वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 12 फरवरी, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनमोदित

2. उपरोक्त परिणाम सेबी (सचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम. 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल ापरीक्षित तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणामों व बसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.meyerapparel.com पर उपलब्ध है। बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

थानः गुरूग्राम दिनांकः 12 फरवरी, 202**2**

बीच, उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में कर्नाटक सरकार से शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए कहा। अदालत ने इसके साथ ही निर्णय आने तक शिक्षण संस्थानों में कक्षाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक द्वेस पहनकर आने पर रोक लगा दी थी। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और अश्विनी दुबे के जरिये निखिल उपाध्याय द्वारा दायर नई जनहित याचिका में केंद्र सरकार को एक न्यायिक आयोग अथवा विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल्यों को सिखाने तथा विद्यार्थियों के बीच भाईचारा, सम्मान, एकता और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के उपाय

सीवीआई ने अनिल देशमुख के सीए से जुड़े नागपुर स्थित 12 परिसरों पर छापा मारा

नागपुर (महाराष्ट्र), (भाषा)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने (सीबीआई) महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज धनशोधन के मामले में नागपुर स्थित उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से जुड़े 12 स्थानों पर शनिवार को छापेमारी की। दिल्ली और मुंबई से सीबीआई क दल श्क्रवार रात नागपुर पहुच और उन्होंने शनिवार सुबह छापेमारी शुरू की। अधिकारी ने कहा, इन 12 स्थलों में देशमुख के सीए के या तो आवास है या उनके कार्यालय परिसर हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्होंने पिछले साल अप्रैल में राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल एक नवंबर को गिरफ्तार किया था और वह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख के खिलाफ 21 अप्रैल, 2021 को प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद निदेशालय ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने आतंकी हमले की निंदा की

जम्मू, (भाषा)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को बांदीपुरा में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। इस आतंकवादी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया और चार अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। उपराज्यपाल ने देर रात ट्वीट किया, मैं हमारे सुरक्षा कर्मियों पर किए गए घृणित आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं। मैं जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारी) जुबैर अहमद शाह की शहीदी को सलाम करता हूं।

वैधानिक सूचनाः पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन मे प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच ग्ड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वार किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या प्रमर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

हस्ता./

(गजेन्दर कुमार शर्मा)

डीआईएनः 08073521





NSE board let Ramkrishna resign without action: Sebi

EY corroborates exchange's claim that COO was the 'Himalayan Yogi', but Sebi not convinced

jayshree.p@livemint.com **NEW DELHI**

he mystery of the "Himalayan yogi" who advised former National Stock Exchange (NSE) boss Chitra Ramkrishna remains unsolved, with the exchange saying it was none other than chief operating officer Anand Subramanian himself—a claim also corroborated by EY, which conducted a forensic audit—while the market regulator did not find the linkage convincing enough.

During the course of investigations, managing director Ramkrishna maintained that in her emails to the third party who went as "rigyajursama", she was taking guidance from a "siddhapurusha" or "paramhansa", her spiritual guide for over 20 years. She asserted that the said person was not Subramanian

"Ramkrishna stated that the third person was not Mr Subramanian; (but) the results of the forensic investigation conducted by EY (asked by Sebi and commissioned by NSE) concluded that the person using the email id 'rigyajursama@outlook.com' was Mr. Subramanian himself," Sebi order stated. NSE sent detailed reports to

the Securities and Exchange Board of India in May and July 2018, stating that

the 'yogi' was Subramanian himself. "The confidential information of NSE were not disclosed to an unknown



Chitra Ramkrishna said that she had in her emails sought guidance from a third party—'rigyajursama', who she says is a 'siddha-purusha' or 'paramhansa'.

entity, but to the Group Operating Officer (GOO), who anyways had access to financial, operational and HR-related information about NSE. Further, NSE confirmed that no damage to the market was caused in any manner due to

responses to Sebi's questions framed in the 3 May 2018 letter," said Sebi in the

Ananta Barua, Sebi whole-time member, wrote in the order that the E&Y report, at best, reveals that the

FAILURE TO DISCHARGE FUNDAMENTAL DUTY

NSE had sent

detailed reports to

that the 'yogi' was

Sebi in 2018, stating

RAMKRISHNA asserted that the 'third person' was not COO Anand Subramanian

SEBI order said the EY probe concluded that Subramanian was using the ʻrigyajusama' ID

SEBI said the board failed to discharge its fundamental duty, which is it be a first level of check

Date: 13.02.2022

such correspondence and that Ms. Ramkrishna confirmed that the third party had not used confidential information for any personal or monetary gain. NSE also provided detailed

unknown person was also well known and close to Subramanian but did not give a conclusive finding that Subramanian was, in fact, the unknown third

"I find that there is no conclusive evidence or finding from the E&Y Report or the documents before me to prove that the unknown person who used the email id 'rigyajursama@outlook.com'

was in fact, Noticee no. 6 (Subrama-

nian)," said Sebi in the order. Saturday's Sebi order also came down heavily on the NSE board, which was aware that Ramkrishna was passing on confidential information to an unknown third party but allowed her to resign instead of initiating action against her.

Sebi said this was a failure of checks and balances at India's largest stock exchange since, at any company, the first level of check is the board, which failed to discharge this fundamental duty. Sebi's 190-page order found the exchange, Ramkrishna, former chief executive Ravi Narain and others in violation of Sebi rules and levied monetary penalties on them. The irregularities pertain to the appointment of

Anand Subramanian, chief operating officer (COO) and adviser to managing director, who was brought in as a consultant and later promoted as COO. Ramkrishna and Subramanian have also been barred from associating with any exchange, depository or market intermediary for three years.

Sebi also highlighted the glaring lack of governance in the leak of NSE's key financial information to a third person and how the board did not flag the issue to the regulator.

India must review its existing FTAs, work on new ones: CII

Ravi Dutta Mishra ravi.dutt@livemint.com

ndia must review its existing trade agreements since Free Trade Agreements (FTAs) signed by India with ASEAN, Japan, and Korea have not helped Indian industry access these markets, the Confederation of Indian Industry (CII) has said amid ongoing trade nego-

tiations with more than 20

countries

Non-tariff measures must be identified and discussions undertaken with partner countries to resolve them for market access, CII stressed in its report 'Achieving \$1 tn Merchandise Exports by 2030: A Roadmap'. New trade agreements with key large markets would help reduce tariff gaps with other supplier nations, the industry body suggested.

"FTAs should not only cover tariff liberalisation but also address non-tariff measures in partner countries. A comprehensive exercise of consultations with industry country by country should be undertaken to identify specific non-tariff measures that hinder Indian exports under the FTA. These should be systematically taken up with the FTA partners," CII

The CII report lamented that the US decision to withdraw the generalized system of preferences (GSP) under the administration of President Donald Trump in 2019 has impacted India's exports from labour-intensive sectors. India should press for the restoration



Non-tariff measures must be identified and discussions should be held with countries. CII said in its report.

The CII report

has identified 14

products as

those that can

contribute the

most to the rise

in exports

of GSP by the US as it is the country's largest export market, CII suggested.

The report has identified 14 products as those that can contribute the most to the increase in exports, on the basis of the potential to gain global share. "These include vehicles, textiles, electrical machinery and

equipment, machinery apparel, chemical products, plastics, and pharmaceuticals," CII said.

On manufacturing, the report highlighted that India has been imposing exces-

sively high import duties on components and intermediates and, as a result, imports of finished products have thrived "discouraging new investments and underdevelopment of a vibrant input ecosystem in the economy".

The government should aim

to encourage the import of intermediate products that add

value to exports, CII suggested. "Overall manufacturing competitiveness in India is impacted by higher costs at every stage of the export process, ranging from starting a business to processes to transport of the products. Labour

productivity in India is low, leading to higher labour costs despite the demographic advantage. All delays and hurdles manifest in higher working capital requirements, lost

orders, longer inventory holdings, and added storage costs,' CII said.

CII also raised the issue of delays in implementing the four labour codes, saying that the laws have been notified but are yet to be notified by the state governments.

IL&FS to resolve debt by March

feedback@livemint.com **NEW DELHI**

L&FS group is all set to resolve debt of ₹55,000 crore by March, the board of the crisis-hit company has stated in its affidavit filed before the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT).

While updating the progress of the resolution, the IL&FS board led by banker Uday Kotak said ₹55,000 crore debt would be resolved through asset monetization, restructuring and initiatives pertaining to insolvency proceedings.

Some of this has already been completed, while the rest is in different stages of resolution, it said in a brief snapshot on the progress made in the $ongoing \,\bar{resolution}\,\bar{process}\,till$ 7 December 2021, and also gave estimates of progress that will be made by March this year.

IL&FS had a total outstanding debt of ₹99,355 crore as of 8 October 2018, and of this, ₹45,500 crore debt is being resolved through debt resolution initiatives by March 2022.

Of this, debt of ₹20,500 crore has already been resolved through monetization, ₹4,000 crore by way of debt discharged



The number of IL&FS's domestic entities is now down to 95. MINT

IL&FS group's

₹55.000 crore

debt would be

monetization,

insolvency

and ₹21,350 crore in cash available across companies and Invit units due to be issued. In addition, the board also expects to resolve ₹5.300 crore through various "transactions approved by the relevant

court/tribunal and pending transaction closure" and ₹4,200 crore from resolution applications filed with courts and pending approvals.

"As of 4 January 2021, the total number of entities in Respondent No 1 (IL&FS) group has reduced to Ill from 302," the affidavit said.

IL&FS's domestic entities have been reduced to 95 from 169, while offshore entities have been reduced to 16 from 133. The Board had informed that it would resolve the issues

resolved via asset restructuring and

ceedings.

of 29 of 60 entities through monetization process; 12 road assets under Invit; 3 assets where concession pacts were terminated and 30 entities where it initiated closure or insolvency pro-

The company had accumulated cash balance of ₹16,742 crore, as of 7 December 2021.

McNally Bharat Engineering Company Limited CIN: L45202WB1961PLC0251B1 Regd. Office: 4 MANGOE LANE, Kolkata 700 001 Website:www.mcnallybharat.com, Email id: mbecal@mbecl.co.in

Phone no: (033) 6628-1212 ent of unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended 31st December, 2021

(Rs. in Lakhs, unless otherwise stated							ierwise stater			
	Standalone				Consolidated					
Particulars	Three months ended		Nine mor	Nine months ended		Year ended Three months ende		ed Nine months ended		Year ended
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1 Total Income from operations	7,372.31	7,304.94	19,874.76	21,284.65	33,278.33	13,562.21	12,881.05	35,729.18	35,232.24	53,185.49
2 Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional items)	113.51	(2,115.30)	(1,358.58)	(6,373.49)	(5,003.57)	69.21	(1,941.39)	(1,380.95)	(6,062.59)	(4,350.36)
3 Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	113.51	(2,115.30)	(1,358.58)	(6,373.49)	(5,003.57)	69.21	(1,941.39)	(1,380.95)	(6,062.59)	(4,350.36)
4 Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	113.51	(2,115.30)	(1,358.58)	(6,373.49)	(5,003.57)	69.21	(1,941.39)	(1,380.95)	(6,062.59)	(4,350.36)
5 Other Comprehensive Income (net of tax)	4.44	0.23	8.88	4.70	17.75		(1.77)	9.88	(27.30)	35.75
6 Total Comprehensive Income for the period	117.95	(2,115.07)	(1,349.70)	(6,368.79)	(4,985.83)	69.21	(1,943.16)	(1,371.07)	(6,089.89)	(4,314.61)
7 Equity share Capital	21,157.08	21,157.08	21,157.08	21,157.08	21,157.08	21,157.08	21,157.08	21,157.08	21,157.08	21,157.08
8 Reserves (excluding Revaluation Reserve)					(13,776.18)	-	-	8		(24,602.10)
9 Earning per Share (EPS) for the period (Face value Rs.10/- per share)	222									72.74
-Basic (Rs.) -Diluted (Rs.)	0.05 0.05	(1.00) (1.00)	(0.64) (0.64)	(3.01)	(2.36) (2.36)	0.04 0.04	(0.92) (0.92)	(0.65) (0.65)	(2.87) (2.87)	(2.11) (2.11)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of BSE (www.bseindia.com) & NSE (www.nseindia.com) and shall also be available on website of the company (www.mcnallybharat.com) By Order of the Board

For McNally Bharat Engineering Company Limited Managing Directo

STL GLOBAL LIMITED

CIN: L51909DL1997PLC088667

Regd. Office: Unit No. 111, Block No. 1, First Floor,

Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065

Tel: 011-26935829. E-mail: investors@stl-global.com. Website: www.stl-global.com

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

<mark>nint</mark> Start-ups

Because only rebels can change the world.



feedback@livemint.com **NEW DELHI**

odrej Properties plans to invest around ₹7,500 crore (\$1 billion) over the next 12-18 months on acquisition and development of new real estate projects.

In an interview, Godrej Properties executive chairman Pirojsha Godrej sounded upbeat on the growth potential in the housing and commercial real estate segments especially in four major markets-Mumbai Metropolitan Region (MMR), Delhi-NCR, Bengaluru and Pune-where the company has a huge presence, "We will invest \$1 billion (around ₹7,500 crore) over the next 12-18 months on development of new projects," Pirojsha said, adding that the planned investments would be in mix of equity and debt.

Godrej Properties, the largest listed realty firm in the last fiscal in terms of sales book-



Godrej executive chairman Pirojsha Godrej.

ings, acquires new projects through outright purchase of land parcels and also forming joint ventures with land own-

Pirojsha said the company acquired three projects in the third quarter of this fiscal and the pipeline is strong.

"Q4 should be good for us in both sales bookings and new project acquisitions. We are likely to close many deals this quarter," he hoped.

In March last year, Godrej Properties had raised ₹3,750 crore through Qualified Institutional Placement (QIP) process as part of its objective to strengthen the company's balance sheet and future business growth.

The company's net debt is ₹313 crore as on 31 December 2021. The debt equity ratio is also only 0.04. When asked about entering

new cities, Pirojsha said: "We are interested in Hyderabad. But its not our top priority. There are huge opportunities in top four key markets where we have a major presence." The company intends to enter Hyderabad in a big way and not just for development of one or two projects, he said.

On operational performance, Pirojsha said the company is likely to achieve an alltime high sale bookings in the 2021-22 financial year, beating last year's record of ₹6,725 crore. "We will have decent growth in sales bookings this fiscal," he said.



Scan the QR code or visit livemint.com

Continuous coverage of the rapidly evolving tech and start-up world Up close with the real changemakers.



FOR LEADERS OF THE NEW ORDER

QUARTER & NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2021

			(Rs. in Lakhs)			
Particulars	Quarter Ended (31.12.2021) Unaudited	Nine Months Ended (31.12.2021) Unaudited	Corresponding Quarter ended in the previous year (31.12.2020) Unaudited			
Total Income from operations (net)	3,375.23	9,068.42	2,483.01			
Total Expenses	3,279.41	8,890.77	2,360.71			
Net Profit /(Loss) for the period	96.46	249.31	122.99			
(before Tax, Exceptional Items)						
Net Profit /(Loss) for the period	96.46	249.31	122.99			
before Tax (after Exceptional Items)						
Net Profit /(Loss)for the period after	96.46	226.81	122.99			
tax (after Exceptional items)						
Total Comprehensive Income for the	96.75	218.97	122.99			
period (Comprising Profit/(Loss) for						
the period (after tax) and Other						
Comprehensive Income (after tax)						
Equity Share Capital	2,722.18	2,722.18	2,722.18			
(Face Value: Rs. 10/- each)						
Reserves (excluding Revaluation		-	_			
Reserve) as shown in the Balance						
Sheet of previous year						
Earnings Per Share (for continuing						
and discontinued operations)						
Basic:	0.36	0.81	0.46			
Diluted:	0.36	0.81	0.46			
Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Lin-Audited Financial Results for the						

The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2021filed with the Stock Exchanges i.e. NSE & BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015 as amended from time to time. The full formats of the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31 2021are available on the company's website at www.stl-global.com and on the Stock Exchanges websites at BSE at www.bseindia.com and at NSE at www.nseindia.com

The Company has analyzed all the relevant parameters associated with the risk due to COVID-19 and is of the opinion that it will not have any material impact on the b and going concern assumptions

Place: Faridabad Date: 12th February, 2022

There were no exceptional and extraordinary items during the quarter and nine months ended 31st December, 2021. For and on behalf of the Board of Directors o

Sh. Sanjiv Kumar Aggarwa

STL Global Limited

(DIN: 00227251